

## Editorial

# Entering in New Year with Scattered Dreams

Every year we are entering in a new year after completion of the last year. Entire human being at global level enters in new year with high profile celebration and full enjoyment. The situation for the BSNL employees is entirely different. The BSNL employees are entering in New Year 2023 with their scattered dreams.

The DOT employees absorbed in BSNL from 01.10.2000 entered in PSUs with many dreams. The dreams of better salary than the government department, better promotional avenues, high jump in carrier through internal limited competitive examination, jobs security and they were in confident that the converted company from government entity will remain financially viable as it was committed by the then government in Centre. They were pleased. It was also committed by the government that the employees who observed in BSNL company will be paid government Pension on par with the other Central Government employees under CCS pension rules 1972. The rule was also amended with insertions of rule-37A to ensure pension on superannuation and family pension in case of death of the employee. All the executive and non-executive employees opted to be absorbed in BSNL with a dream to get better pension that whatever they would have it after retirement from government department.

In the year 2006 the then government through a cabinet decision taken back that the cabinet decision of Sept. 2000 and decided to pay only 60% of amount of the pension to BSNL employees after retirement and the rest 40% has to be born by the BSNL Company.

Our mighty organization NFTE (BSNL) fought against this unjustified decision of the Government and after 10 years of regular struggle of the workers, the full pension was restored in July 2016 by a cabinet decision of the union government.

The dreams of the absorbed employees started scattering and in the year 2020 the commitments of the government in respect of job security was also taken back and 78468 executive and non-executive employees were sent out from the BSNL through VRS on the name of revival package. About sixty thousand employees both executive and non-executive below the age of 50 years are left and they are still serving in the BSNL. More than 60% non-executive employees are facing stagnation for even 10 or 12 years and rest are also at the verge of stagnation. The young employees with higher education also joined in BSNL after 2002. They entered in the BSNL as TTA and now they have been designated as Junior Engineers are also not less sufferers. They joined this BSNL with the feeling that in this Navratan Company, they will get a better carrier progression and better salary with better working atmosphere but their dreams are also scattering after VRS. All the promotional scopes have been snatched by the top management in name of restructuring of organization set-up and man power distribution. All the live and sanctioned posts of promotional cadres were abolished after implementation of VRS. Now they are in unsafe Zone.

The wages of employees have not been revised which was due from 1st January 2017. Thus, the entire dreams to get the better salary and carrier progression are scattered.

A common dream of entire workforce to procurement and implementation of need-based technology such as rolling out the 4G/5G spectrums are also seems to be scattered. The workers of BSNL have gone through regular struggle for the rolling out the 4G/5G spectrum to compete with the private operations, who have entered in the market with 5G services.

The wage cut has been imposed upon the workers for agitation to demand the implementation of services based on 4G/5G spectrums.

One side management blames the workers for not earning revenue to bring the company in profit

other side the need-based Technologies are not being provided to attract the customers and the workers are threatened to be punished if they will go on agitation. Thus, the dreams of the workers have scattered in all the way.

There is no smile seen on the face of the workers in BSNL. They have lost the patience and living under threat as their future is unsecured. In this circumstances the unions and associations have to take some special initiative to protect the right of workers and save the company.

The government is adamant to experiment to make in India policy on the cost of BSNL workers. The workers never oppose. The 'Swadeshi' policy of the Government of India but the company is losing the faith of customers and market share is reducing day by day due to non-availability of high speed data on BSNL services. The 4G/5G is the need of the time in telecom sector. In the absence of high speed data the earning of more revenue is not possible.

We hope that the government will feel the lot of suffering of the workers for their no fault and subsidize the BSNL to meet the expenditure on wage revision and other staff welfare measures.

The NFTA BSNL is always looking forward for the betterment of situation and always ready to March ahead to bring the company as well as the workers to come out from the critical situation.

The crisis will come and go but we should welcome the new year 2023 with full swim and with a hope that the dreams of the workers maybe come back as reality in near future.

**NFTE Zindabad**  
**Workers Unity Zindabad**

## बिखरते सपने के साथ नव वर्ष में प्रवेश

प्रत्येक वर्ष साल की समाप्ति के पश्चात नए वर्ष का आगमन होता है। वैश्विक आधार पर लोग उच्च स्तरीय समारोह एवं पूर्ण प्रफुल्लता के साथ नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए स्थिति भिन्न है। यह कर्मचारी वर्ग अपने बिखरे हुए सपनों को सहेजते हुए मायूस मन से नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं।

दूरसंचार विभाग के कर्मचारी 01.10.2000 को जब भारत संचार निगम लिमिटेड में प्रवेश कर रहे थे तो वह अनेकों सपने संजोए हुए थे। यह सपने अच्छे वेतन मान, सरकारी विभागों से अच्छे पदोन्नति के रास्ते और सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उच्चस्तर की पदोन्नति, नौकरी की सुरक्षा के साथ वे आश्वस्त थे कि दूरसंचार विभाग द्वारा बनाए जा रहे भारत संचार निगम लिमिटेड की आर्थिक सुदृढ़ता बनी रहेगी क्योंकि भारत सरकार के मंत्री परिषद के अनुमोदन से इस तरह का लिखित वादा कर्मचारियों से किया गया था। वह अति प्रसन्नता के साथ निगमित महकमें में अपने कार्य करने को राजी हो गए। वह इसलिए भी आश्वस्त थे कि सरकार ने निगम में समाहित होने के बावजूद सरकारी पेंशन भुगतान की गारंटी की है तथा इसके लिए सरकार ने पेंशन अधिनियम 1972 को संशोधित करते हुए एक नई उपविधि 37 ए बनाया गया, जिसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि समाहित कर्मचारी सरकारी पेंशन के हकदार होंगे तथा उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके आश्रित को विधि अनुकूल पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।

सन् 2006 में तत्कालीन सरकार ने अपने मंत्री परिषद के अनुमोदन के द्वारा सर्वप्रथम कर्मचारियों को आघात पहुंचाते हुए सितंबर 2000 के भारत सरकार के मंत्रीपरिषद के फैसले को दरकिनार करते हुए यह निर्णय लिया कि बीएसएनएल के कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन राशि का 60% ही भारत सरकार देगी शेष 40% की राशि बीएसएनएल को अपने राजस्व से देनी होगी।

हमारा सशक्त संगठन एनएफटीई (बीएसएनएल) ने लगातार इस फैसले का विरोध करते हुए 10 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद जुलाई 2016 में सरकार को बाध्य किया और भारत सरकार के पुनः संपूर्ण पेंशन की राशि भारत सरकार द्वारा भुगतान करने की गारंटी की।

यहीं से कर्मचारियों के सपनों का सरकार द्वारा भी बिखराव शुरू हुआ तथा सन 2020 आते-आते नौकरी की सुरक्षा का सरकारी वादा भी बिखर गया और वीआरएस के नाम पर 78468 एक्सिक्यूटिव एवं नान-एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों को सेवा से बाहर कर दिया गया। लगभग 60000 कर्मचारी वीआरएस के बाद जो 50 वर्ष से कम उम्र के थे वो सेवा में बने रहे। मुसीबत इतने से नहीं टली, समय पर वेतन समझौता लागू नहीं होने के कारण आज की तारीख में 60% कर्मचारी 10 या 12 वर्षों से स्टैगनेशन का सामना कर रहे हैं। तथा बचे हुए कर्मचारी के सपने के सामने भी निकट भविष्य में स्टैगनेशन का खतरा दस्तक दे रहा है। सन 2002 के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त युवा भी टीटीए जो बाद में जूनियर इंजीनियर कहलाए, की भर्ती की गई। वह भी इस महकमे में काफी सपने संजो कर प्रवेश किए। वो इस सोच के साथ इस नवरत्न कंपनी में शामिल हुए कि किसी भी सरकारी विभाग से अच्छा वेतन मान पाएंगे साथ ही पदोन्नति के रास्ते से उच्चपदों तक जाने का अवसर प्राप्त करेंगे। परंतु पदोन्नति के सारे रास्ते वीआरएस के बाद छीन लिये गए। क्योंकि वीआरएस के पूर्व विभाग में समस्त स्वीकृत एवं जीवंत पदों को एक झटके में प्रबंधन ने समाप्त कर दिया, अब वे युवाकर्मी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

कर्मचारियों के वेतन मान का पूर्ण निर्धारण होना 1 जनवरी 2017 से लंबित है और उस पर प्रबंधन तथा सरकार का कोई सापेक्ष नजरिया नहीं है। समस्त कल्याणकारी नीतियां समाप्त कर दी गईं। इस प्रकार बीएसएनएल के समाहित कर्मचारी या नव-नियुक्त कर्मचारी सभी के सपने बिखर गए हैं।

कर्मचारियों ने यह प्रबंधन की नीतियां देखी कि महकमे में राजस्व की कमी के कारण वेतन पुनर्निर्धारण नहीं हो रहा है। इस स्थिति से उबरने के लिए कर्मचारियों ने बीएसएनएल के लिए उच्च माध्यमिक तकनीक पर आधारित सेवाएं संचालित करने की मांग की, जिसके तहत 4जी/5जी स्पेक्ट्रम पर आधारित मोबाइल सेवा तथा डाटा सेवा मुहैया कराने के लिए कर्मचारियों ने लगातार संघर्ष किया। इन संघर्षों में भाग लेने के कारण कर्मचारियों के वेतन काट लिए गए तथा अन्य तरीकों से भी प्रताड़ना दी गई। इस प्रकार कर्मचारियों के अधिक राजस्व उपार्जन के सामूहिक सपने भी बिखर गए।

आज बीएसएनएल के किसी भी कर्मचारी के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर नहीं आती है। उन्होंने धैर्य खो दिया है और भयग्रस्त हैं। वह महसूस करते हैं कि उनका भविष्य असुरक्षित हो गया है।

इस स्थिति के मद्देनजर सभी यूनियन एवं एसोसिएशन को कुछ विशेष कदम उठाने होंगे ताकि कर्मचारियों के अधिकार को सुरक्षित किया जा सके तथा बीएसएनएल कंपनी को बचाया जा सके। भारत सरकार ने एक अड़ियल रुख अपनाया है कि बीएसएनएल में उच्च तकनीक का इस्तेमाल स्वदेशी कलपुर्जे का ही किया जाएगा। इस संबंध में कर्मचारी भारत सरकार के स्वदेशी नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं अपितु उनका कहना है कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि उच्च स्तरीय तकनीकी का अविष्कार एवं उत्पादन हमारे देश में हो जिससे वैश्विक स्तर पर दूर संचार के क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा होगा।

कर्मचारियों का कहना है कि स्वदेशी के नाम पर जो उच्च तकनीक के इस्तेमाल पर रोक लगी है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को उच्च गति का डाटा संप्रेषण नहीं मिलता है और वह क्षुब्ध होकर बीएसएनएल का साथ छोड़ रहे हैं। आज बाजार में बीएसएनएल की साख कम होते जा रही है साथ ही कर्मचारी भी सपनों के बिखरने के कारण कुंठित हो रहे हैं। इसलिए कर्मचारी यह मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार स्वदेशी उत्पादन को विकसित करें परंतु इसके कीमत पर बीएसएनएल को डूबने की स्थिति में ना लाएं। भारत सरकार इस अवधि में बीएसएनएल को होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई करें।

हम आशा करते हैं कि सरकार कर्मचारियों की कठिनाई और कंपनी के सेवाओं में गिरावट को महसूस करेगी और इसके लिए सरकार कंपनी को आर्थिक सहायता देगी।

एनएफटीई (बीएसएनएल) हमेशा कर्मचारियों के हित रक्षा के लिए अग्रणी भूमिका निभाते रही है और आज भी हम पहली कतार में खड़े होकर संघर्ष के लिए तैयार हैं।

कठिनाइयां आएंगी और जाएंगी परंतु आम कर्मचारी साथियों को नए साल 2023 का गर्म जोशी से स्वागत करते हुए इस आशा और विश्वास के साथ नए साल में प्रवेश करना है कि उनके बिखरे हुए सपने वास्तविकता में तब्दील होंगे और गरिमामय स्थिति की पुनर्बहाली होगी।

**एनएफटीई जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद**